

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून:दिनांक 04 जनवरी, 2017

**विषयः—** राज्य में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुयी क्षतियों के सम्बन्ध में एस0डी0आर0एफ0 मानकों में अनुमन्य राहत राशि में स्थायी रूप से वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्यतया भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 12 आपदाओं यथा: बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चकवात, भूकम्प, बादल फटना, हिमस्खलन, कीट आक्रमण, ओलावृष्टि, सूनामी, शीतलहरी एवं पाला में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि के मानकों के अनुरूप राहत राशि दी जाती है। समय-समय पर इन दरों में घटित आपदा एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप राज्य स्तर पर भी वृद्धि की गयी है। सामान्यतया राज्य स्तर पर की गयी वृद्धि एक मानसून सत्र (15 जून से 30 सितम्बर) के लिये की जाती है।

2— दिनांक 17.12.2016 को मा0 मंत्रिमण्डल की सम्पन्न बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से हुयी क्षतियों में आपदा राहत की दरों में स्थायी वृद्धि किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित मदों में एस0डी0आर0एफ0 मद में अनुमन्य राहत राशि के अतिरिक्त राहत राशि दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(क)— वर्तमान में मानव क्षति के लिये राज्य आपदा मोर्चन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से रु0 4.00 लाख की राहत राशि अनुमन्य है। इसमें स्थायी रूप से वृद्धि करते हुए भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति होने पर प्रति मानव क्षति रु0 1.00 लाख की धनराशि सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) के रूप मृतक के विधिक वारिसान को अतिरिक्त रूप से अनुमन्य की जाएगी।

(ख)— भवन क्षति के लिये एस0डी0आर0एफ0 मानकों में मैदानी क्षेत्रों में रु0 95100.00 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रु0 101900.00 की राहत राशि का प्राविधान है। तथा वर्तमान मानसून सत्र में हेतु इसमें वृद्धि करते हुए भवन क्षति पर रु0 2.00 लाख की धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार की ओर से रु0 1.00 लाख अतिरिक्त राहत राशि दी जा रही है।

(ग)– उक्तानुसार दी जा रही राहत राशि की दर में स्थायी रूप से वृद्धि करते हुए इसको बढ़ाकर भवन की क्षति के लिये ₹0 3.00 लाख की धनराशि अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ)– पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के चिन्हिकरण के लिये प्रत्येक उप-जिलाधिकारी के स्तर पर 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथव उनके प्रतिनिधि एवं 01 अवर अभियन्ता को नामित किया जायेगा। समिति द्वारा जो भी भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये जायेंगे, ऐसे सभी भवनों को प्रति भवन ₹0 3.00 लाख की राहत राशि अनुमन्य की जाएगी। राहत अनुमन्य करने के साथ ही सभी असुरक्षित चिन्हित किये गये भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे भवनों की सामग्री पर भवन स्वामी का अधिकार होगा।

(च)– समिति द्वारा जिन भवनों को मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किया जाएगा ऐसे परिवारों को ₹0 4000.00 मासिक किराया भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। जो अधिकतम 06 माह के लिए होगा।

(छ)– उक्तानुसार राहत राशि की अनुमन्य दरों में स्थायी रूप से वृद्धि से होने वाले व्यय भार के सम्बन्ध में आबकारी एवं खनन विभाग के द्वारा लिये जा रहे राजस्व पर कुछ अतिरिक्त उपकर (सैस) आरोपित करते हुये एक निधि का गठन किया जा रहा है, तथा निधि के गठन व इसके क्रियाशील होने से पूर्व अनुमन्य राहत राशि की दरों में की गयी वृद्धि पर होने वाले व्ययभार का वहन मा10 मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.–209 NP /XXVII(5)/2015-16, दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या—२४९५ /XVIII-(2)/2016-04(27)/2010TC, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2— सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— प्रभारी सचिव, मा० मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखण्ड शासन।
- 5— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 6— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
- 7— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 8— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 10— राज्य सूचना अधिकारी, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12— निदेशक, कोषागार, 24, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 13— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
- 14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव